वह किस स्थान पर होगा यह अभी तय नहीं किया गया है। यह उसी समय तय होगा, जब कि प्लानिंग कमिशन सारी पंचवर्षीय योजना मान लेगा।

सामुदायिक रेडियो सेट

*१४४६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि १९५५-५६ में सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेट लगाने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ सहायक अनुदान देने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कोई योजना भेजी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना में सन् १९५५-५६ के लिये ४०० पंचायती रेडियो सेट मांगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को फ्री रेडियो सेट १५० रुपये के हिसाब से या सेटों के कुल दाम का ५० प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जायेगा।

श्री के० सी० सोधिया : एक एक सेट का सालाना खर्चा कितना होता होगा मय उसकी कीमत के ?

डा० केसकर : सेट्स का दाम सवा सौ से डढ़ सौ रुपये तक होता है लेकिन कम्युनिटी सेट्स में सेट के अलावा कुछ एक्सेसरी यंत्रों की भी जरूरत होती है जैसे लाउड स्पीकर वगैरह। सब मिला कर दो सौ से तीन सौ रुपये तक दाम हो जाता है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस गांव वालों को भी कुछ मदद देनी पड़ेगी ?

डा० केसकर : सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटों को यह दे देती है। यह उनके ऊपर है कि वे गांव वालों से पैसा लें, या उनको मुफ्त में भी दे दें। बहुत सी सरकारें गांव वालों को वैसे भी दे देती हैं, कुछ आधा दाम लेती है। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीका अपनाया जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा और किन किन राज्यों ने ऐसे सेट्स मांगे हैं, और सरकार ने देने का वचन दिया है ?

डा० केसकर : सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश ने मांगे हैं और उनको दे भी दिये गये हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ट्रावनकोर-कोचीन और आसाम ने भी मांगे हैं।

श्री के० सी० सोधिया : एक एक सेट कितने कितने गांवों की जरूरत पूरी करेगा ?

डा० केसकर : वह सुनने वालों की जरूरत पूरी करेगा।

श्री कामत : मध्य प्रदेश में इन सटों के वितरण के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सलाह देती है या नहीं ?

डा० केसकर : जब हम यहां से राज्य सरकारों को सेट देते हैं तो हमारा उनको यही आदेश होता है कि सेट्स की मरम्मत और रोजमर्रा के चलने के बारे में राज्य सरकारों को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। खाली सेट देने से काम नहीं होता। लेकिन हमेशा यह देखना कि राज्य सरकारें इस मामले में क्या कर रही हैं बहुत कठिन है। तब भी जहां तक हो सकता है हम देखते हैं कि सेटों की मरम्मत के लिये और उनका रोजमर्रा का चलना देखने के लिये इंस्पेक्टर या मिकैनिक वगैर नियुक्त किये जायें।

श्री विभूति मिश्र : क्या केन्द्रीय सरकार विविध स्टेटों को मांगने पर ही सैट देती है या केन्द्रीय सरकार हर एक स्टेट सरकार के लिये अपनी तरफ से कोटा एलाट करती है ?

डा० केसकर : मांगने पर देती है । मगर उसकी विना यह है । सब राज्यों के इनफारमेशन मिनिस्टरों और डाइरेक्टर्स आफ इनफारमेशन की यहां एक सभा हुई थी । उसके अनुसार हर एक स्टट ने अपना अपना कोटा बांध लिया था कि हमको इतनी आवश्यकता पड़ेगी । उस पर उन सब को सूचना दे दी गई कि अब सैट तैयार हो सकते हैं और मिल सकते हैं, आपको जब जरूरत हो फौरन मंगा लें ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या विन्ध्य प्रदेश ने अपना कोटा बांधा हुआ है ?

Rubber Factory

*1449. **Shri Punnoose** : Will the Minister of **Commerce and Industry** be please d to refer to the replies given to Starred Question No. 2488 on the 2 2nd April, 1955 and state :

(a) whether any applications have since been received from the Private Sector to start a Rubber Factory in Travancore-Cochin State with the collaboration of the foreign undertaking of Goodrich;

(b) if so, the names of the applicants; and

(c) the terms and conditions proposed by them ?

The Minister of Industries (Shri Kanungo) : (a) to (c). Certain discussions have taken place with a firm's representative for the starting of a rubber factory in the Travancore-Cochin State. A formal application under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 is awaited.

Shri Punnoose : May I know whether it is a foreign firm that has applied for this ?

Shri Kanungo : No, it is Indian firm with foreign collaboration.

Shri Punnoose : How much of that investment will be Indian and how much foreign.

Shri Kanungo : That is still in the stage of discussion and has not been finalised yet.

Shri Punnoose : May I know whether there is a proposal before the Government to produce tyres in the present rubber factory in Travancore-Cochin and also whether it is a fact that this proposal is being shelved for this alliance with the foreign company ?

Shri Kanungo : There is no such proposal from the Travancore-Cochin State.

Shri Punnoose : Is it not a fact that the chief of the rubber factory was called to Delhi and there was a conference between higher circles and that there was a definite proposal that 12, coo tyres could be produced per year ?

Shri Kanungo : There have been discussions off and on, but then there is no definite proposal from the State Government to that effect.

Shri Nanadas : May I know whether the Central Government would call for applications from the State Governments ?

Shri Kanungo : The Central Government welcomes proposals from all State Governments.

Shri Punnoose : Is there only one....

Mr. Speaker : Order, order. The hon. Member has put nearly half a dozen supplementaries.

Shri Punnoose : I will ask only one more question.

Is there only one applicant for this rubber factory business or more than one applicant ?

Shri Kanungo : There has been no application yet. It is only a proposal.

Mr. Speaker : The question list is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Chemical Fertilizers

*1432. **Shri D. C. Sharma** : Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to lay a statement on the Table of the House showing the kinds and quantities of chemical fertilizers proposed to be imported during 1955-56 ?

The Minister of Commerce (Shri Karmarkar) : A state-